



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1970 (भाद्र 14, 1892)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1970 (BHADRA 14, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं।—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 15th July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 695	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 3851
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1063	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	561
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	997
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1093	भाग III—खंड 2—एवम् कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसों	343
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	809
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	3095	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	153
		पूरक संख्या 36—	
		29 अगस्त 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1485
		9 अगस्त 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1501
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	695	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3851
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1063	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	561
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	997
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1093	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta.	343
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	809
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3095	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	153
		SUPPLEMENT No. 36	
		Weekly Epidemiological Reports for week ending 29th August 1970	1485
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 9th August 1970	1501

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अभिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 1970

सं० एफ० 1(3) एन० एस०/70—केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा यह निदेश देती है कि वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की 14 मार्च, 1970 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443 के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये गये 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र (दूसरा निर्गम)—बैंक क्रम, 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचतपत्र (तीसरा निर्गम)—बैंक क्रम और 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचतपत्र (चौथा निर्गम) बैंक क्रम पहली अगस्त, 1970 से प्राधिकृत एजेंट (बैंक) योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये एजेंटों की मारफत बेचे जायेंगे और उन्हें 1-1/4 प्रतिशत कमीशन दिया जायगा। फिर भी, यदि कोई निवेशकर्ता आवेदनपत्र लेने वाले कार्यालय में सीधे आवेदनपत्र देना चाहे तो वह ऐसा कर सकेगा।

पी० एन० मालवीय, अनुसचिव

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1970

संकल्प

सं० 29/2/69-टैक्स (ए०)—विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के संकल्प सं० 29/2/69-टैक्स (ए०) दिनांक 4 जुलाई, 1969 के क्रमांक 8 के सामने दिये गये नाम "श्री पी० के० बिरला" के स्थान पर "श्री आर० के० बिरला" पढ़ा जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, योजना आयोग, मन्त्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क बोर्ड, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों, संसद-पुस्तकालय और वस्त्र आयुक्त, बम्बई, को भेजी जाये।

संकल्प

दिनांक 14 अगस्त 1970

सं० 29/2/69-टैक्स (ए०)—भारत सरकार ने, चौधरी राम सेवक, उप-मन्त्री विदेशी व्यापार मंत्रालय को भारत के राज-पत्र भाग 1 दिनांक 4 जुलाई, 1969 में प्रकाशित उनके संकल्प

सं० 29/2/69-टैक्स (ए०) दिनांक 4 जुलाई, 1969 द्वारा पुनर्गठित सूती वस्त्र मलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त करने का विनिश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, योजना आयोग, मन्त्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक, प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड, उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड, लोक सभा तथा राज्य सभा के सचिवालयों, संसद-पुस्तकालय और वस्त्र आयुक्त, बम्बई को भेज दी जाए।

एच० के० बंसल, उप-सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1970

चाय समिति पर पी० सी० बरुआ समिति का प्रतिवेदन

सं० 2(10)-प्लान्ट (ए०)/70 (बी० सी०)—संकल्प सं० एफ० 28 (63) प्लान्ट (ए०)/66, दिनांक 9 जनवरी, 1967 द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय ने चाय उद्योग के सभी पहलुओं से सम्बन्धित आर्थिक परिस्थितियों तथा समस्याओं की व्यापक समीक्षा करने और चौथी योजना अवधि में सही आधार पर इसके उपयुक्त विकास हेतु आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए श्री पी० सी० बरुआ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति के विचारार्थ विषय निम्नोक्त थे :

- (क) देश अथवा विदेशों में खपत के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए परिणामस्वरूप तथा गुणात्मक वृद्धि करने के लिए उत्पादन स्तर में (खेती क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रति हैक्टर की उपज में सुधार आदि करके) मागपायों को विकसित करने के प्रश्न की जांच करना;
- (ख) उद्योग के समक्ष विद्यमान तथा इसके उपयुक्त विकास में रुकावट डालने वाली विपणन, वित्त तथा गवेषणा सम्बन्धी तात्कालिक समस्याओं की जांच करना;
- (ग) किसी ऐसे अन्य पहलू की, जो समिति की राय में इस जांच के व्यापक उद्देश्य से सम्बन्धित हो, जांच करना।

2. नवम्बर 1968 में समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन किया। प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार ने सावधानी से विचार किया।

3. संकल्प के अनुबन्ध 1 में दी गई सिफारिशों स्वीकार कर ली गई हैं और क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

4. संकल्प के अनुबन्ध 2 में दी गई सिफारिशों उनके प्रत्येक के सामने दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए स्वीकार की गई हैं।

5. अनुबन्ध 3 में दी गई सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई हैं।

6. अनुबन्ध 4 में दी गई सिफारिशों अथवा निष्कर्षों को सरकार द्वारा नोट कर लिया गया है और अनुबन्ध 5 में दी गई सिफारिशों स्वीकार नहीं की गई हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धों को भेज दी जाए और इसे सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एस० आर० रघुपति, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध-1

चाय उद्योग पर पी० सी० बहआ समिति की वे सिफारिशें जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और जो क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं

पी० सी० बहआ समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों की सिफारिशों के सारांश में दिए हुए क्रमांक

3. सामान्य उद्देश्य, प्रत्येक बाग की आवश्यकता के अनुसार, उत्तम रोपण सामग्री के साथ पुनरीक्षण, प्रतिस्थापन और/अथवा विस्तार के रूप में, प्रति वर्ष कुल क्षेत्र के 3 प्रतिशत की दर पर नए पौधे लगाना होना चाहिए।

(कंडिका 1.7)

6. समिति सिफारिश करती है कि उद्योग को उर्वरकों की पूर्ति इस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिए कि वह अन्ततः दिसम्बर के अन्त तक बागानों को पहुंच जाए।

(कंडिका 1.22 तथा 1.24)

8. समिति चाय गोष्ठी (जून 1967) में की गई सिफारिशों का समर्थन करती है कि सिंचाई के प्रयोजनार्थ चाय बागानों को पानी पर्याप्त पूर्ति हेतु उपयुक्त योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों को तैयार करे। राज्य सरकारों को चाय बागानों में भूमिगत जल के अधिकतम उपयोग की सम्भावनाओं पर सर्वेक्षण भी करवाने चाहिए।

(कंडिका 1.34)

10. भारत के अन्य भागों में भी पुनरोपण उपदान देने के लिए औचित्य है। यह उपदान प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होगा जो स्थल की रूपरेखा पर निर्भर करेगा। पुनरोपण के लिए उपदान उद्योग पर प्रभार के रूप में नहीं होना चाहिए।

(कंडिका 1.43 तथा 1.45)

12. दार्जिलिंग में हाल में संकट को देखते हुए, जिसका प्रभाव उस जिले के उद्योग पर पड़ा है, वहां के बागानों के लिए विशेष राहतें दिए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(कंडिका 1.48 तथा 1.52)

15. हरी चाय के उत्पादकों को उनके उत्पादन तरीकों में सुधार कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे मोरावको को वहां की पसन्द की चाय देने की स्थिति में हो सकें।

(कंडिका 1.67)

16. एक्साइज जोन 1 में उत्पादित हरी चाय पर लगा उत्पादन शुल्क भारत में हरी चाय के सभी उत्पादकों पर लागू होना चाहिए।

(कंडिका 1.68)

19. तुरन्त तैयार हो सकने वाली चाय पर, प्रयोगशाला स्तर पर प्राप्त हुआ अनुसन्धान निष्कर्ष काफी उत्साह-वर्धक है। अतः इस प्रक्रिया के और आगे विकास करने के लिए प्रयोगिक स्तर पर और भी परीक्षण किए जाने चाहिए।

(कंडिका 2.45 तथा 2.46)

26. अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर में एक लाभप्रद प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली कार्यवाही विनिश्चय करने के लिए इस पूरे विषय का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.24, 3.26)

27. राजस्व शुल्क जैसे निर्यात शुल्क आदि लगा कर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं बढ़ाए जा सकते क्योंकि ग्राहक द्वारा निलामियों में अपना मूल्य निर्धारित करते समय ऐसे शुल्कारोपणों का भी ध्यान रखा जाता है। यदि निर्यात शुल्क को हटा दिया जाए अथवा घटा दिया जाए तो निर्यात-ग्राहक को अपने कार्य चालन में और अधिक सुविधा होगी।

(कंडिका 3.31, 3.32)

28. चाय बोर्ड पर लीबियन गादामों को सम्भालने का भार नहीं डाला जाना चाहिए।

(कंडिका 3.34)

33. निर्यात शुल्क प्रभारों का चाय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आय को बनाए रखने के लिए चाय पर विद्यमान निर्यात शुल्क को बिल्कुल हटा देना चाहिए।

(कंडिका 3.59, 3.60)

34. निर्यात शुल्क के साथ उत्पादन शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है, जिसकी निर्यात अभिमुख उद्योग के निर्यातों पर वापसी नहीं होती।

(कंडिका 3.64)

41. समिति सुझाव देती है कि अविशिष्ट संवर्धन के प्रभार का मूल्यांकन करने हेतु अन्य उत्पादक देशों के साथ मिल कर तथा व्यापारियों की सहायता से संयुक्त सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

(कंडिका 3.114)

42. विदेशों में खरीदी गई चाय के अधिकांश अंश को गुण तथा मूल्य पर विचार करके खरीदा जाता है। अतः हमारी चाय

- के गुण में निरन्तर सुधार करना तथा उन्हें प्रतियोगी मूल्यों पर चाय दे सकने की हमारी क्षमता को बढ़ाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह अत्यावश्यक है कि उन देशों में, जहाँ एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाता है, विदेशी ग्राहकों तथा भारतीय चाय उद्योग के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क विकसित किए जाएं तथा उन्हें सुदृढ़ किया जाए।
(कंडिका 3. 118-3. 120)
43. हमें अविशिष्ट संवर्धन से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और अविशिष्ट संवर्धन पर वर्तमान व्यय को बनाए रखते हुए भी हमें एकल राष्ट्रीय संवर्धन पर काफी अधिक व्यय करना चाहिए। ऐसे प्रचार से एक दो वर्ष के भीतर परिणामों की आशा नहीं की जा सकती और हमें पांच दस वर्ष की प्रचार योजना बनानी चाहिए।
(कंडिका 3. 122)
45. समिति सिफारिश करती है कि कार्य-पद्धति का विनिश्चय और योजनाओं के कार्यचालन का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक बाजार सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। बाहरी देशों में प्रचार सामग्री के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में चाय बोर्ड को आवश्यक धन-राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
(कंडिका 3. 132)
50. निर्यात शुल्क उत्पादक को प्राप्त होने वाले विक्रय मूल्य को कम कर देता है और इससे उत्पादन की कुल लागत बढ़ जाती है। समिति निर्यात शुल्क को पूर्णतः समाप्त करने की सिफारिश करती है।
(कंडिका 4. 22-4. 24)
56. सरकार को, चाय बोर्ड की योजनाएं चलाने के लिए समय पर पर्याप्त धनराशि दिया जाना सुनिश्चित करने के कदम उठाने चाहिए। और समय के भीतर वस्तु स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
(कंडिका 4. 74)
72. इस प्रकार गठित बोर्ड को सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और चाय उद्योग से सम्बन्धित मामलों में उसके विचारों तथा सिफारिशों पर अधिक तथा तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
(कंडिका 5. 19)
73. चाय बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष के लिए होना चाहिए और इसमें अन्य दो वर्ष बढ़ाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
(कंडिका 5. 21)
76. हमारे योजना लक्ष्यों के सन्दर्भ में विकास और अनुसन्धान के महत्व को ध्यान में रखते हुए दो नई स्थायी समितियाँ अर्थात् चाय विकास समिति और अनुसन्धान समिति स्थापित की जानी चाहिए।
(कंडिका 5. 27)
77. समिति प्राक्कलन समिति के इस विचार का समर्थन करती है कि बोर्ड आगामी वर्षों में चाय कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रभावी उपाय करने की स्थिति में न हो सकेगा और यह सिफारिश करती है कि इस खाने में बोर्ड के खर्च में क्रमशः कमी की जाए यह उद्योग के सामान्य सुधार तथा विकास तक ही अपने को सीमित रखे।
(कंडिका 5. 29, 5. 30)

अनुबन्ध-2

चाय उद्योग पर पी० सी० बरुआ समिति की सिफारिशों, जो उनके समक्ष दी गई टिप्पणियों के अधीन स्वीकार की गई हैं

पी० सी० बरुआ समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों की सिफारिशों के सारांश में दिये हुए क्रमांक	सिफारिशें	टिप्पणी
2.	31-3-66 को कुल चाय क्षेत्र के 41.6 प्रतिशत क्षेत्र में 21-50 वर्ष आयु वर्ग की झाड़ियाँ हैं और 31.4 प्रतिशत में 50 वर्ष पुरानी झाड़ियाँ हैं। इन्हें शीघ्र ही प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये। (कंडिका 1. 6)	इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई कि चाय के अन्तर्गत जिस क्षेत्र में प्रतिस्थापन होना है वह अभी प्रक्रमवार किया जायेगा। सरकार ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि 30 वर्ष से अधिक पुरानी झाड़ियों को, यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापित किया जाये।
5.	समिति की यह राय है कि:— (क) चाय उगाने के लिये किसी चाय बागान भूमि का पुनर्ग्रहण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। (ख) चाय के अन्तर्गत भूमि और चाय के अन्तर्गत न आने वाली भूमि के बीच चाय अनुदान के भीतर किसी विशिष्ट सम्बन्ध का रखना वांछनीय नहीं है।	सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई कि वह भूमि जो वस्तुतः चाय खेती के अन्तर्गत है, उसका पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा। उस भूमि के सम्बन्ध में जो चाय के अन्तर्गत नहीं है, राज्य सरकार को सिफारिश अभिस्तावित कर दी जायेगी।

पी० सी० बरुआ

समिति के प्रति-

वेदन के निष्कर्षों

की सिफारिशों के सारांश

सिफारिशें

टिप्पणी

में दिये हुए क्रमांक

(ग) चाय बागानों को विस्तार के लिए उपयुक्त सभी भूमि रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके अनुषंगी प्रयोजनों के लिए आवश्यक पर्याप्त भूमि रखने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

(घ) चाय अनुदानों के भीतर भूमि का पुनर्गठन वांछनीय नहीं है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले उपायों की सिफारिश करती है।

(कड़िका 1. 17 तथा 1. 18)

7. नाशिकीटमार तथा घासपातनाशी दवाएं देश में मुलभूतता से प्राप्त होनी चाहिए ताकि उद्योग को यथावश्यक रूप में वे मिल सकें।

(कड़िका 1. 27 तथा 1. 29)

9. दार्जिलिंग का, जो बढ़िया चाय का क्षेत्र है, उत्पादन वर्ष, 1960 से निरन्तर गिर रहा है। इस जिले के चाय के पौधों में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पौधे 51 प्रतिशत हैं जो अलाभकर वर्ग में आते हैं और अन्य 33 प्रतिशत पौधे 21-50 वर्ष के आयु-वर्ग में हैं। उनका तुरन्त पुनरोपण करना आवश्यक है। इस जिले के लगभग आधे बागान घाटे में या मामूली लाभ में चल रहे हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि अलाभकर क्षेत्रों में पुनरोपण तथा बदली करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 3000 रु० प्रति एकड़ की दर से और उपज में हुई हानि के सम्बन्ध में प्रति एकड़ अतिरिक्त 1000 रु० की दर से उपदान दिया जाये।

(कड़िका 1. 38, 1. 40—41)

11. आय कर प्राधिकारियों द्वारा विकास भत्ते के प्रयोजनार्थ अनुमत अधिकतम सीमा को, जो मैदानी और पहाड़ी बागानों के लिए 10,000 रु० तथा 12,5000 प्रति हैक्टर है, पुनरीक्षित करके क्रमशः 12,500 रु० तथा 15,000 रु० प्रति हैक्टर कर दिया जाये।

(कड़िका 1. 48)

13. अलाभकार चाय बागानों के पुनर्विकास के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया है।

(कड़िका 1. 56-1. 57)

14. मद्रास सरकार की योजना लघु उत्पादकों की समस्याओं के लिए आशावर्धक दृष्टिकोण की परिचायक है। इसके साथ समुचित क्षेत्र-सलाहकार सेवा की भी व्यवस्था

स्वीकार कर ली गई। ग्रामोवसीन के उत्पादन के लिए शीघ्रता से लाईसेंस देने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गयी। दार्जिलिंग क्षेत्र में उपदान के परिमाण पर आगे विचार तथा विनिश्चय किया जाना है।

सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गयी। कानून में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति के सामान्य पर्यवेक्षणों को नोट कर लिया गया है और चाय बोर्ड द्वारा यदि विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तो उन पर विचार किया जायेगा।

सहकारी चाय फैक्टरियों के लिए इस प्रकार की सहायता मंजूर कर दी गयी है। कीनिया योजना भारत के लिए उपयुक्त नहीं है।

पी० सी०
वरुआ समिति
के प्रतिवेदन के
निष्कर्षों की
सिफारिशों के
सारांश में दिये
हुए क्रमांक

सिफारिशें

टिप्पणी

- की जानी चाहिये। फिर भी चाय बोर्ड-द्वारा कीनिया योजना का ध्यानपूर्वक अध्ययन युक्तिसंगत हो सकता है। (कंडिका 1. 63)
20. दोनों गवेषणा केन्द्रों में समुचित प्रयोगशाला उपकरणों की, जिन पर गवेषणा की प्रगति निर्भर करती है, कमी है। यदि हम यह आशा रखें कि हमारा चाय उद्योग अत्यधिक प्रतियोगी विश्व बाजार में अपने पांव पर खड़ा हो जायेगा तो चाय गवेषणा के लिए निश्चित वित्तीय सहायता अपेक्षित है। हमारे दो प्रमुख प्रतियोगियों के वैज्ञानिकों की तुलना में हमारे वैज्ञानिकों को अत्यधिक कठिनाइयां हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि गवेषणा के लिए न केवल अधिक धन और पर्याप्त विदेशी मुद्रा ही प्रदान की जाये अपितु आयातों की क्रियाविधि को भी यथावश्यक सुकर बना देना चाहिये ताकि अपेक्षित उपकरण समय पर तत्काल और आसानी से प्राप्त किये जा सकें। (कंडिका 2. 44-2. 48)
21. चाय गवेषणा संस्था, जिसका आंशिक वित्तपोषण सरकार करती है, प्रतिवर्ष अपनी आय का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ है और जब दीर्घावधि आधार पर आयोजना बनानी होती है तो यह एक गम्भीर बाधा बन जाती है। इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है (क) ब्लाक अनुदान, अथवा (ख) उद्योग पर उपकर द्वारा। समिति पहले तरीकों को तरजीह देती है परन्तु सरकार यदि हमारे तरीके को अनुकूल समझे तो सम्पूर्ण निबल आय का उपयोग केवल चाय गवेषणा के लिए ही किया जाना चाहिये। यू० पी० ए० सी० आई० के मामले में कार्यवाही भिन्न रूप में की जा सकती है। (कंडिका 2. 50-2. 54)
22. गवेषणा में सामंजस्य बनाये रखने की दृष्टि से किये गये कार्य की समीक्षा और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विचारों के आदान-प्रदान के लिए विशेषज्ञों की एक लघु वैज्ञानिक परामर्शदाता समिति स्थापित की जानी चाहिये, जिस में वैज्ञानिक और उत्पादकों के प्रतिनिधि हों। (कंडिका 2. 58)
23. उत्तर पूर्व भारत में जब से चाय की खेती आरम्भ हुई तब से चाय नीलामों में बेची जाती रहीं हैं। इसे उत्पादक भी तरजीह देते हैं और यह बिक्री का सर्वोत्तम माध्यम है। परन्तु उत्पादकों के सम्मिलित में भारी हानि होती है, अतः हर प्रकार की सम्भव बर्बादी को रोकने के लिए सम्मिलित की क्रियाविधि में सुधार किया जाना चाहिये। (कंडिका 3. 1-3. 6)
- गवेषणा कार्य के लिए समुचित प्रयोगशाला उपकरणों की महता मान्य है। तदनुसार सिफारिश की सिद्धान्त-रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जहां आयातों का सम्बन्ध है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अपनायी जाने वाली नीति चाय गवेषणा प्रयोगशालाओं द्वारा भी अपनाई जा सकती है।
- इस पर एक समिति अलग से विचार कर रही है और उसके प्रतिवेदन पर भी अलग से विचार किया जा रहा है।
- इस पर एक समिति विचार कर रही है जिसके प्रतिवेदन पर अलग से विचार किया जा रहा है।
- सिद्धांत रूप में स्वीकृत। चाय बोर्ड को इस मामले पर उत्पादकों तथा निर्यातकों के साथ बातचीत करनी चाहिये।

पी० सी०
ब्रुआ समिति
के प्रतिवेदन के
निष्कर्षों की
सिफारिशों के
सारांश में
दिये हुए क्रमांक

सिफारिशें

टिप्पणी

29. कलकत्ता तथा कोचीन दोनों पतनों के पतन प्रभार धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस में कोई और वृद्धि होने से चाय के निर्यात अधिक मंहगे और कठिन हो जायेंगे और हो सकता है कि इससे जहाजी सेवाओं को भारतीय पतनों की उपेक्षा करने की प्रेरणा मिले। (कंडिका 3. 39)
30. कोचीन पतन पर गोदामों, घाट पर जगह और अन्य सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। कलकत्ता पतन पर होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ब्रिटेन को सीधे चाय भेजने के लिए वैकल्पिक पतन के रूप में कांडला पतन की सम्भाव्यताओं का पता लगाना युक्तियुक्त है। (कंडिका 3. 41, 3. 42)
31. चूंकि पैलेटीकृत पोत लदानों की प्रतिशतता उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है अतः रेलवे को माल-डिब्बों पर पैलेटीकृत चाय के आवागमन की समस्या की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये। चाय के पोत-लदान से सम्बन्धित सभी पतनों को पैलेटीकृत पोत-लदानों की व्यवस्था के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए सरकार द्वारा भी सहायता दी जानी चाहिये। (कंडिका 3. 45—3. 49)
32. चाय के निर्यातों को सुधारने के लिए विभिन्न विदेशी बाजारों विशेषतः आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड के सम्बन्ध में पोत-लदान अबसर बेहतर होने चाहिये। (कंडिका 3. 50—3. 53)
- यद्यपि चाय पर लगने वाले पतन प्रभार में वृद्धि को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय चाय के निर्यातों पर लगने वाले पतन प्रभार के पुनरीक्षण पर विचार करते समय चाय के निर्यात पर उसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखेगा।
- जहां तक कोचीन पतन का संबंध है वहां पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं। पतन पर घाट की क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं और फोर्क लिफ्टों की व्यवस्था कर दी गयी है।
2. जहां तक कलकत्ता का संबंध है, इस समय अनुभव हो रही कठिनाइयां तलाकपेण के प्रतिबन्धों के कारण हैं और निकट भविष्य में फरक्का बैरेज तथा हल्दिया डाक सिस्टम के चालू हो जाने पर इनके दूर हो जाने की आशा है। पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित होने वाली चाय के निर्यातों के लिए कलकत्ता स्वाभाविक मार्ग है और मामान्यतः इसके यातायात का कांडला को दिशान्तरण वांछनीय नहीं है। फिर भी आपवादिक परिस्थितियों में चाय के निर्यातों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में है।
- सम्बन्ध विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं का विकास पैलेटीकृत खेपों को बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं करता परन्तु ऐसा अनुमान है कि कन्टेनर सेवा से जरूरत पूरी हो जायेगी।
- कोचीन से डबलिन तथा राटरडम को नियमित सुधे जहाजी सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं। भारतीय जहाजरानी निगम द्वि-मासिक जहाजी सेवा प्रदान करता है और समय-अनाराल को शीघ्र ही कम करके महीने में एक बार जहाजी सेवा प्रदान करने का उनका विचार है। निकट भविष्य में इस सेवा को न्यूजीलैंड तक बढ़ाने की उनकी योजना है।

31. डा० एल० आर० वैद्यनाथ,
मेनेजर,
भारतीय तांबा सूचना केन्द्र, कलकत्ता ।
32. डा० एम० एन० पार्थसारथी,
भारतीय सीमा-जस्ता सूचना केन्द्र, कलकत्ता ।
33. श्री जी० डी० बिनानी,
अध्यक्ष,
भारतीय अलॉय-धातु उत्पादक संघ, कलकत्ता ।
34. फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज,
नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।
35. योजना आयोग का प्रतिनिधि ।
36. सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय का प्रतिनिधि ।
37. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय
कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि ।
38. संचार मंत्रालय (डाक तार बोर्ड) का प्रतिनिधि ।
39. सुरक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि ।
40. रेलवे मंत्रालय (रेल बोर्ड),
नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।
42. वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि ।
42. श्री ए० कृष्णन,
निदेशक,
खान तथा धातु विभाग—सदस्य सचिव ।

2. परिषद् के उपरोक्त सदस्यों का कार्य-काल दो वर्ष की कालावधि के लिये होगा ।

3. मलाहकारी परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य, परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने हेतु सड़क/रेल द्वारा जाने वाली यात्राओं के लिये, समय-समय यथा संशोधित, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय जापन संख्यांक एफ० 6(26)ई० 4/59, दिनांक 5-9-60 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे । यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, आदि के प्रयोजनों के लिये, गैर-सरकारी सदस्यों को प्रथम ग्रेड के सरकारी कर्मचारियों के समरूप समझा जायेगा और उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित, वित्त मंत्रालय के कार्यालय जापन संख्यांक 5/4 1/ई० 4(बी०)/62 दिनांक 14-8-62 में, अधिकथित यात्रा भत्ते की संशोधित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प में सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्री मंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा मिलिटरी सचिवों, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध को संसूचित किया ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

शुद्धि-पत्र

सं० 3(6)/69-मेटल-1—भारत के राजपत्र के असाधारण भाग I, खण्ड 1, दिनांक 12 जून, 1970 में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्यांक 3(6)/69-मेटल-1 दिनांक 12 जून में निम्न-लिखित शुद्धियाँ की जाएँ ।

- (1) पृष्ठ 530 पर पंक्ति 2 तथा 7 में से अल्प विराम “(.)” लुप्त किया जाए;
- (2) पृष्ठ 530 पर पंक्ति 7 में, “एंब” के लिए शब्द “एवं” प्रतिस्थापित किया जाए ।
- (3) पृष्ठ 530 पर पंक्ति 13 में, शब्द “शुल्क” के लिए शब्द “शुल्क” प्रतिस्थापित किया जाए ।
- (4) पृष्ठ 531 पर पंक्ति 2 में, शब्द “की” के स्थान पर शब्द “रखी” प्रतिस्थापित किया जाए;
- (5) पृष्ठ 532 पर लाइन 18 में, शब्द “बीमा” के पश्चात अल्पविराम “(.)” जोड़ा जाए;
- (6) पृष्ठ 532 पर पंक्ति 25 में शब्द “होगा” के पश्चात अल्प विराम “(.)” प्रतिस्थापित किया जाए;
- (7) पृष्ठ 532 पर पंक्ति 29 में शब्द “है” के पश्चात अल्प विराम “(.)” जोड़ा जाए;
- (8) पृष्ठ 532 पर पंक्ति 31 में, शब्द “या” के स्थान पर शब्द “था” प्रतिस्थापित किया जाए;
- (9) पृष्ठ 533 पर पंक्ति 8 में, शब्द “हुए” के पश्चात अल्पविराम “(.)” जोड़ा जाए और पंक्ति 9 में, शब्द “है” के आगे पूर्ण विराम चिन्ह (।) के स्थान पर अर्द्ध विराम चिन्ह “(;)” प्रतिस्थापित किया जाए;
- (10) पृष्ठ 533 पर लाइन 13 में, शब्द “मुल्य” के स्थान पर शब्द “मूल्य” प्रतिस्थापित किया जाए और पृष्ठ 533 पर ही पंक्ति 14 में, शब्द “अतिरिक्त” के पश्चात अल्पविराम “(.)” जोड़ा जाए ।

महेन्द्र स्वरूप भटनागर, अवर सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1970

संकल्प

सं० ई० एल० दो-1(8)/69—दिनांक 12 फरवरी, 1968 के समसंख्यक संकल्प के साथ पठित, इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल० दो-1(7) 65, दिनांक 19 जनवरी, 1968 के अधीन स्थापित केन्द्रीय बिजली मलाहकार परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में पुनः गठित की जाती है :—

- | | |
|---|---------|
| 1. केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत उपमंत्री | सदस्य |
| राज्यों और संघीय प्रदेशों के मंत्री | |
| 3. सिंचाई और विद्युत मंत्री, उड़ीसा | सदस्य |
| 4. मंत्री, मार्षजनिक निर्माण विभाग, तमिल नाडु | सदस्य |
| 5. विद्युत मंत्री, आंध्र प्रदेश | सदस्य |

6. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
7. उद्योग और विद्युत मंत्री, जम्मू और कश्मीर	सदस्य
संसद सदस्य	
8. श्री जहानुद्दीन अहमद, संसद् सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
9. श्री बी० नारायणन, संसद् सदस्य, (लोकसभा)	सदस्य
10. श्री राजावेंकटप्पा नायक, संसद् सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
11. श्री आर० सुरेंद्र रेड्डी, संसद् सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
12. श्री धीरेश्वर कलिता, संसद् सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
13. श्री एम० आर शर्मा, संसद् सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
14. श्री देवेंद्र विजय सिंह, संसद् सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
15. श्री राम चंद्र उलका, संसद् सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
16. श्री पी० वेंकटमुब्बैया, संसद् सदस्य, (लोकसभा)	सदस्य
17. श्री ब्रह्मानंद पांडा, संसद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
18. श्री पृथ्वी नाथ, संसद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
19. श्री नारायण प्रसाद चौधरी, संसद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
20. श्री पंडरी नाथ सीतारामजी पाटिल संसद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
21. डा० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय संसद् सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
22. बाद में अधिसूचित किया जाएगा ।	
राज्य बिजली बोर्ड	
23. अध्यक्ष, असम राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
24. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
25. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
26. अध्यक्ष, मैसूर राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
27. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सदस्य
भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि	
28. सचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	सदस्य
29. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	सदस्य
30. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
31. पेट्रोलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
32. इस्पात और भारी इन्जीनियरी मंत्रालय (लोहा और इस्पात विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
33. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सह-कारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य

34. औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का एक प्रतिनिधि

35. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का एक प्रतिनिधि

36. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

अधिकरणों आदि के प्रतिनिधि

37. अध्यक्ष, हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० भोपाल

38. अध्यक्ष, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०

39. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, अथवा उसका प्रतिनिधि

40. भारतीय बिजली प्राधिकरण मंत्र का एक प्रतिनिधि

41. अध्यक्ष, भारतीय विद्युत उपकरण निर्माता मंत्र अथवा उसका प्रतिनिधि

42. अवैतनिक महामंचिव, कार्यकारिणी समिति, नेशनल टनेज क्लब आफ फार्मेर्स निदेशक (विदेशी मुद्रा और विद्युत), सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस परिषद् का सदस्य-मंचिव होगा ।

अध्यक्ष परिषद् की बैठकों में किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसे वह आवश्यक समझे, आमन्त्रित कर सकता है ।

2. पर्याप्त द्रुत चक्रानुक्रम को सुनिश्चित करने के लिये, परिषद् की समयावधि एक पारी में 2 वर्ष तक होगी ।

3. (क) परिषद् निम्नलिखित विषयों पर विचार कर सुझाव देगी :—

(1) बिजली के उत्पादन, सम्भरण और वितरण से संबंधित तथा बिजली उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली बिजली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित वे मामले जो कि इस के पास केंद्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा विचारार्थ भेजे जायें ।

(2) बिजली के उत्पादन, सम्भरण और वितरण से संबंधित तथा बिजली उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित वे मामले जिन्हें अध्यक्ष की स्वीकृति से परिषद् का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से एजेंडे में सम्मिलित करना चाहे ।

(3) बिजली के सम्भरण और वितरण से संबंधित कोई और विषय जिसे जन-हित और सुविधा के लिये उपयुक्त समझा जाए ।

(ख) यह परिषद् पूर्ण रूप से परामर्शदात्री होगी ।

(ग) कर्मचारी वर्ग, अनुशासन और नियुक्तियों से संबंधित मामले इस परिषद् के मामलों प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे ।

4. (क) परिषद् अपनी बैठक एक साल में कम से कम एक बार अवश्य बुलायेगी ।

(ख) बिजली उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित खाम-खाम समस्याओं पर सरकार को सलाह देने के लिये अध्यक्ष परिषद् की समितियों अथवा उप-समितियों स्थापित कर सकता है।

(ग) यदि कोई सदस्य बैठक में किसी विषय पर विचार-करना चाहे तो उसे इसके लिये सचिव को पूरे एक महीने का नोटिस देना चाहिए और जिन विषयों पर वह विचार-विमर्श चाहता है, उनका संक्षेप में वर्णन कर देना चाहिये। सचिव एजन्डे को कम से कम 10 दिन पहले सदस्यों में परिपत्रित करेगा और साथ ही यथा संभव हर एक सदस्य पर आपन भी भेजेगा। यदि तात्कालिक विषयों पर विचार किया जाना हो तो उन्हें बिना नोटिस के ही परिषद् में प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु इसके लिये अध्यक्ष की स्वीकृति लेनी होगी। अध्यक्ष किसी विषय को अपने विवेक से अस्वीकृत कर सकता है।

(घ) परिषद् की बैठकों की कार्यवाही गोपनीय होगी लेकिन मामान्यतः कार्यविवरण का एक संक्षिप्त सार तैयार किया जायेगा और प्रैम को दे दिया जायेगा।

5. परिषद् के सदस्य की बैठकों में भाग लेने के लिये यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेंगे जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को संबंधित सदस्यों, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रियों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव

योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक को पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

बी० बी० चारी, सचिव

श्रम, रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय

श्रम और रोजगार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1970

संकल्प

स० 31/186/69-एल० आर०-4—संकल्प सख्या 31/18/69-एल० आर०-4, दिनांक 9 दिसम्बर, 1969 में, पैरा दो के नीचे बैकल्पिक नामों के क्रमांक 1 में "श्री टी० एस० स्वामीनाथन" के स्थान पर "श्री एन० एम० वकील रत्ना जाय"।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड (i) में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों, स्वचालन समिति के अध्यक्ष और अन्य सभी सम्बंधितों को भेजी जाय।

पी० एम० नायक, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 16th July 1970

No. F. (13)-NS/70.—The Central Government hereby directs that with effect from 1st August, 1970, 7-Year National Savings Certificates (II Issue)—Bank Series, 7-Year National Savings Certificates (III Issues)—Bank Series and 7-Year National Savings Certificates (IV Issue)—Bank Series, issued by the Government of India in terms of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. GSR 443 dated the 14th March, 1970 will be available for sale through agents appointed under the Authorised Agents (Bank) Scheme who will be paid a commission of 1½ per cent. However, where an investor wishes to tender an application direct at the receiving office he will be free to do so.

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 15th July 1970

RESOLUTION

No. 29/2/69-Tex.(A).—The name against S. No. 8 of the Ministry of F.T. & Supply Resolution No. 29/2/69-Tex.A dated the 4th July, 1969, may be read as "Shri R. K. Birla" instead of "Shri P. K. Birla".

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Union Territories, All Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, Cabinet Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Excise and Customs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, Library of Parliament and the Textile Commissioner, Bombay.

The 14th August 1970

RESOLUTION

No. 29/2/69-Tex(A).—The Government of India have decided to appoint Chowdhary Ram Sewak, Deputy Minister, Ministry of Foreign Trade as Vice-Chairman of the Cotton Textiles Consultative Board as re-constituted by their Resolution No. 29/2/69-Tex(A), dated the 4th July, 1969, published in the Gazette of India, Part I, Section 1 on 4th July 1969.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments. All Union Territories, all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, Cabinet Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Excise and Customs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, Library of Parliament and the Textile Commissioner, Bombay.

H. K. BANSAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 24th July 1970

RESOLUTION

REPORT OF THE P. C. BOROOAH COMMITTEE ON THE TEA INDUSTRY

No. 2(11)-Plant(A)/70(BC).—By a resolution No. F. 28(63) Plant (A)/66, dated the 9th January, 1967, the Government of India in the late Ministry of Commerce set up a Committee under the Chairmanship of Shri P. C. Borooah to undertake a comprehensive review of the economic conditions and problems of the tea industry in all its aspects and make recommendations regarding the measures required to be taken for its appropriate development on the right lines dur-

ing the Fourth Plan period. The terms of the reference of the Committee were as under :—

- (a) to look into the question of devising ways and means for the quantitative as well as qualitative increase in production (such as through extension of acreage and improvement of yields per hectare) levels required to meet the rising demand for consumption whether at home or abroad;
- (b) to look into the urgent problems of marketing, financing and research that are facing the industry and which may be standing in the way of its appropriate development; and
- (c) to look into any other aspect which in the Committee's opinion is germane to the broad purpose to this enquiry.

2. In November, 1968, the Committee submitted to Government its report. The recommendations made in the report have been under careful consideration of the Government.

3. The recommendations of the Committee listed in Annexure I to the Resolution have been accepted and are already in varying stages of implementation.

4. The recommendations of the Committee listed in Annexure II to the Resolution are accepted subject to the remarks appearing therein against each.

5. The recommendation listed in Annexure III has been accepted in principle.

6. The recommendations or observations of the Committee listed in Annexure IV have been noted by Government and those appearing in Annexure V have not been accepted.

ORDER.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

K. S. RAGHUPATHI, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

RECOMMENDATIONS OF THE P. C. BOROOAH COMMITTEE ON THE TEA INDUSTRIES WHICH HAVE BEEN ACCEPTED AND ARE IN VARIOUS STAGES OF IMPLEMENTATION

Reference to S. No. in the Summary of Conclusions and Recommendations of the Report of P. C. Borooah Committee

3. The general aim should be to undertake new plantings at the rate of 3% of the total area annually, in the form of replantings, replacements and/or extensions, depending on individual needs, with good planting material. (Para 1.7)

6. The Committee recommends that supply of fertiliser should be ensured to the industry to reach estates by the end of December at the latest. (Paras 1.22 & 1.24)

8. The Committee endorses the recommendations made at the Tea Seminar (June 1967) that the Central Government should persuade the concerned State Governments to work out suitable schemes for adequate supply of water to tea estates for the purposes of irrigation. The State Govts. should also undertake surveys on the possibilities of harnessing sub-soil water in tea estates. (Para 1.34)

10. There is a case for giving replantation subsidy to other parts of India also. The subsidy vary from place to place depending on topographical conditions. The subsidy for replanting should not be a charge on the industry (Paras 1.43 & 1.45)

12. Special reliefs should be considered for gardens in Darjeeling in view of the recent disaster that has befallen the industry in that District. (Paras 1.48 & 1.52)

15. Producers of green tea should be encouraged to modify their manufacturing methods so that they are in a position to offer Morocco the type of tea acceptable to them. (Para 1.67)

16. The excise duty on green tea produced in Excise Zone I should be applicable to all producers of green tea in India. (Para 1.68)

19. Research findings, at Laboratory level, on instant tea are encouraging. Further experiments should therefore, be undertaken on a pilot scale for further development of the process. (Paras 2.45, 2.46)

20. The entire subject should be studied in greater depth to decide on the course to be taken to promote an advantageous reaction in the international price level. (Paras 3.24—3.26)

27. International prices cannot be raised by introduction of fiscal levies such as export duty, as such imports are taken into account by the buyer while determining his bid at the auctions. If the export duty is abolished or reduced, the export buyer will have more flexibility in operation. (Paras 3.31, 3.32)

28. The Tea Board should not be saddled with the responsibility of taking over the Libyan warehouse. (Para 3.34)

33. Export duty charges do not affect the international price of tea. The existing export duty on tea should be entirely abolished to maintain our export and foreign exchange earnings. (Paras 3.59—3.60)

34. There is no justification for the imposition of an export duty together with an excise duty, which is not refunded on exports on an export-oriented industry. (Para 3.64)

41. The Committee suggests that independent surveys should be conducted, jointly with other producing countries and with the help of the trade, to assess the effectiveness of generic promotion where they are being undertaken. (Para 3.114)

42. The major proportion to tea purchased abroad is bought on consideration of quality and price. Constant improvement of the quality of our teas and our ability to offer them at competitive prices are, therefore, of utmost importance. It is necessary that the direct link between buyers abroad and the Indian tea industry should be developed and strengthened in countries where unimational campaigns is undertaken. (Paras 3.118—3.120)

43. We should not be content with generic promotion, and the outlay on unimational promotion should be substantially augmented without prejudice to the present expenditure on generic promotion. Such campaigns must be conceived in terms of five or ten year periods as we cannot expect results in one or two year's time. (Para 3.122)

45. The Committee recommends that periodical market surveys should be undertaken to determine the line of action and to evaluate the operation of the schemes. Necessary funds should be made available to the Tea Board in terms of foreign exchange for the production of publicity materials in countries abroad. (Para 3.132)

56. The export duty reduces the sale realisation of the producer and thereby adds to the gross cost of production. The committee recommends a total abolition of export duty. (Paras 4.22—4.24)

66. Government should take steps to ensure timely release of adequate funds for the operation of the Tea Board Schemes and also review the corpus in time. (Para 4.74)

72. The Board so constituted should be recognised by Govt. as an expert body and given greater weight and prompt attention to its views and recommendations, in matters relating to the tea industry. (Para 5.19)

73. The tenure of the Chairman, Tea Board should be for at least a period of 3 years with provision to extend it by another 2 years. (Para 5.21)

76. Two new standing Committees viz., the Tea Development Committee and the Research Committee should be set up in view of the importance of development and research in the context of our plan targets. (Para 5.27)

77. The Committee endorses the view of the Estimates Committee that the Board may not be in a position to undertake effective welfare measures for the tea workers in years to come and recommend that the Board's expenditure on this account should be gradually reduced. It should confine itself to the General improvement and development of the industry. (Para 5.29—5.30)

ANNEXURE-II

RECOMMENDATIONS OF THE P. C. BOROOAH COMMITTEE ON TEA INDUSTRY WHICH ARE ACCEPTED SUBJECT TO THE REMARKS APPEARING AGAINST EACH

Reference to S. No. in the summary of Conclusions and Recommendations of the Report of the P. C. Borooah Committee

Recommendations	Remarks
2. 41.6% of the total tea area as on 31-3-66 is in the 21—50 year age group while another 31.4% consist of bushes which are over 50 years old. These need to be replaced soon. (Para 1.6)	Accepted with the modification that the areas under tea which need to be replaced will be in phases for the present. Govt. has already agreed for the replacement of bushes which are more than 30 years old, if they require replacement.
5. The Committee is of the opinion that :— (a) Resumption of any tea garden land suitable for growing tea is not in the interest of national economy. (b) It is not desirable to lay down any specific relationship between land under tea and that not under tea within a tea grant. (c) Tea Estates should be allowed to retain all land suitable for expansion and also allowed to retain sufficient land necessary for its ancillary purposes. (d) Resumption of land within tea grants is not desirable; and (e) Recommends measures to be taken by Government, Central and States. (Paras 1.17 & 1.18)	Accepted in principle, that land which is actually under tea cultivation is not to be resumed. In respect of other lands not under tea, the recommendation will be commended to State Governments.
7. Pesticides and weedicides should be freely available in the country so that supplies can be obtained by the industry as and when required. (Paras 1.27 & 1.29)	Accepted Steps will be taken for speedy licensing of gammoxene production.
9. The production of Darjeeling quality tea area has been declining since 1960. With 51% of the district teas—over 50 years of age, classed as uneconomic and another 33% in the 21—50 years age group, replanting is urgently needed. Nearly half the estates in the district have been running at a loss or at a marginal profit. The Committee, therefore, recommends, a subsidy at the rate of 3,000/- per acre and additional Rs. 1,000 per acre for loss of revenue from crop, as an incentive to replant and replace uneconomic areas. (Paras 1.38 & 1.40-41)	Accepted in principle. Quantum of subsidy in the Darjeeling area has to be examined further and decided.
11. The ceiling allowed by Income Tax Authorities for the purpose of development allowance, should be revised from Rs. 10,000 and Rs. 12,500 per hectare for plains and hills gardens to Rs. 12,500 and Rs. 15,000 per hectare respectively. (Para 1.48)	Accepted in principle. Necessary amendments to law will be considered by Government.
13. To rehabilitate the uneconomic tea estates measures have been suggested. (Paras 1.56 & 1.57)	The general observations of the Committee have been noted and specific proposals if submitted by the Tea Board will be examined.
14. The Madras Government's Scheme has shown to be a promising line of approach for the small growers' problems. It should be further supplemented by an adequate field advisory service. A careful examination of the Kenya Scheme by the Tea Board may, however, be worthwhile. (Para 1.63)	Such assistance for co-operative tea factories has been agreed to. Kenya scheme is not suitable to India.
20. Adequate laboratory equipment on which progress of research depends are lacking in the two research centres. Positive financial support for tea research is required if we expect our tea industry to hold its own in the present highly competitive world market. Our scientists are at a distinct disadvantage in comparison with those of our two main competitors. The Committee, therefore, recommends that not only should more funds, and also adequate foreign exchange be provided for research, but the procedure for imports, wherever necessary, should be streamlined to make it possible to obtain urgently and easily from abroad, the required equipment in time. (Paras 2.44—2.48)	The importance of adequate laboratory equipments for research work is recognised. Accordingly the recommendation is accepted in principle. As regards imports, whatever policy is followed by the C.S.I.R. may be followed by the Tea Research Institutions.
21. T.R.A. which is partly financed by Government suffers from the inability to forecast their income from year to year and this is a serious handicap when planning must be done on a long-term basis. This can be solved in two ways by (a) a block grant, or (b) a levy on the industry. The Committee prefers the former but if the latter finds favour with the Government, the entire net proceeds should be utilised exclusively for tea research. UPASI's case may require to be dealt with differently. (Paras 2.50—2.54)	This is under separate consideration of a Committee the report of which is being examined separately.

Recommendations	Remarks
<p>22. A small scientific consultative Committee of experts should be set-up with scientists and representatives of the producers for interchange of ideas, reviewing and evaluating the work done with a view to co-ordinating research. (Para 2.58)</p>	<p>This is under consideration of a Committee the report of which is being examined separately.</p>
<p>23. Tea has been sold by auctions ever since it was planted in North East India. It is preferred by producers and it provides the best available medium of sale. But the producers loose heavily on sampling and, therefore, the procedure of sampling should be streamlined to avoid all possible wastage. (Paras 3.1—3.6)</p>	<p>Accepted in principle. Tea Board should pursue the matter with producers and exporters.</p>
<p>29. Port charges have been steadily rising both at Calcutta and Cochin. Any further increase will make tea exports more costly and difficult and may induce shipping lines to by-pass Indian ports. (Para 3.39)</p>	<p>While increases in port charges on tea cannot be completely ruled out, the Ministry of Shipping and Transport will take into account the likely impact on exports of tea while considering any revision in the port charges on tea exports.</p>
<p>30. It is necessary to expand warehousing, berthing and other facilities at the Cochin port. It is worthwhile to examine the possibilities of Kandla port as an alternative outlet for direct shipment teas for the U.K. in view of the difficulties at Calcutta port. (Paras 3.41 & 3.42)</p>	<p>So far as Cochin port is concerned adequate facilities exists. Steps are being taken to augment the berthing capacity at the port and forklifts have been provided.</p>
<p>31. As the percentage of palletised shipments may be expected to grow substantially in the next few years, the Railways should give immediate attention to the problem of movement of palletised teas on wagons. Government should also give necessary assistance to all ports concerned with tea shipments to equip themselves with modern facilities to handle palletised shipments. (Paras 3.45—3.49)</p>	<p>2. As regards Calcutta, difficulties experienced at present due to draft restrictions are expected to be overcome with the commissioning of Farakka Barrage and the Haldia Dock system in the near future. Calcutta is the natural outlet for exports of tea produced in the eastern region and it is not normally desirable to divert this traffic all the way to Kandla. However, in exceptional circumstances the Port of Kandla is in position to provide the necessary facilities for the export of tea.</p>
<p>32. In order to improve exports of tea to various markets abroad shipping opportunities should in particular improve for Australia, New Zealand, Ireland and the Netherlands. (Paras 3.50—3.53)</p>	<p>The development of transport facilities by the concerned Department does not cater to large scale adoption of palletised consignments, but the container service it is anticipated would fulfil the need.</p>
<p>38. Tea bags are increasing in popularity in sophisticated countries and may catch-on in India. Their production in India should be encouraged for export and home consumption. (Para 3.100)</p>	<p>Regular direct sailings to Dublin and Rotterdam are already available from Cochin. The Shipping Corporation of India also provides bi-monthly service from Malabar to Australia and they intend shortly to increase its frequency to one sailing a month. They have plans to extend this service to New Zealand in the near future.</p>
<p>44. At least 2% of the total foreign exchange earned from the export of tea should be set aside for all tea promotion. For efficient control of promotional activities a small Central Committee may be set up with four members including officials and representatives of the trade to sanction the promotional schemes, and once they have been approved, funds including foreign exchange should automatically be released for their effective operation. We are gratified to learn that the Administrative Reforms Commission has also made a similar recommendation. (Paras 3.130—3.131)</p>	<p>The need for promotion of tea bags for export is accepted.</p>
<p>46. In countries where intensive promotion is taken up, it may be necessary to have campaign and public relations officer to maintain liaison with packers distributors, consumers, etc. the press and Journals. Generally speaking, proper market surveys should be carried out with the help of consultants and executed with the help of expert advertising and public relations agencies. This is necessary for a highly organised and sophisticated market. (Para 3.135)</p>	<p>There is no need to have a separate ceiling for publicity. Any reasonable proposal for expenditure on publicity will be considered on merits.</p>
<p>49. There has been a continuous decline in the profitability of the tea industry. The rate of new plantings and replantings has not been at the desired level because the industry has not been allowed to retain sufficient surplus to plough back. The policy of taxation followed by the Central and State Governments together with the various statutory obligations imposed on the industry is mainly responsible for the decline in the profitability. (Paras 4.14 & 4.15)</p>	<p>Accepted and concrete schemes will be considered on merits.</p>
<p>55. The frequent upward revision of excise duty has become a strain on the working resources of producers and could be overcome if the Bonded warehouse system is extended to tea. Government should consider this sympathetically. (Para 4.21)</p>	<p>The policy of taxation followed by the Central and State Governments is based on certain overall considerations and in the national interest in the context of the prevailing economic conditions. The policy is regularly reviewed and suitable changes are effected taking into consideration the general conditions of major industries. The decline in the profitability of the tea industry cannot be attributed to taxation policy of the Central and State Governments.</p>
	<p>The setting up of bonded warehouses will be helpful to the Tea Industry. The incidence of excise duty cannot be considered in isolation and in 1970-71.</p>
	<p>Budget overall relief has been provided to the industry.</p>

Recommendations	Remarks
57. It is necessary to give some relief on the Excise duty also at least in the current year pending reclassification of Excise Zone suggested. (Para 4.20)	The setting up of bonded warehouses will be helpful to the Tea Industry. The incidence of excise duty cannot be considered in isolation and in 1970-71 budget overall relief has been provided to the industry.
58. The Kerala Sales Tax is a heavy burden on the industry in the South. The West Bengal Sales Tax Act provides for exemption from payment of Sales Tax subject to certain conditions and at the first point of sale there is no sales tax liability. If the Kerala Government adopted a similar procedure it would lessen the burden on the producers and would also encourage them to support Cochin auctions. (Para 4.28-4.29)	The question is under review in consultation with the State Government.
59. The Committee endorses the view of the Tea Finance Committee that the rate of tax on the agricultural portion of the composite income should not exceed the rate of tax on the non-agricultural portion of it. (Para 4.36)	The observation of the Committee has been passed on to State Governments.
60. The Housing Subsidy Scheme has been of very little practical help to the industry. Unless Government of India makes available funds for these loans and subsidies immediately it will not be proper for it to expect the industry to fulfil its statutory obligations. (Para 4.46)	The matter has been taken up for consideration and funds are being provided.
61. The cost of construction of labour houses in the plantations should be allowed as a revenue expenditure for assessment of income tax, the Committee also feels that the statutory rate of building at 8% should be reduced to 4%. (Para 4.47)	The suggestion to treat expenditure on labour houses as revenue expenditure is not acceptable to Government. The question of reduction in the statutory rate of building is already under consideration of the Labour, Employment & Rehabilitation Ministry.
62. The Government should take over the responsibility of supplying foodgrains to tea garden labour and arrange to distribute them through fair price shops as in South India. Alternatively, Government should themselves set up rationing centres in the tea estates for such distribution. (Para 4.53)	No difficulty has come to the notice of the Tea Board or Government but the matter has been commended to State Governments.
63. The industry has not been able to build up reserves because of rising costs, rising tax liabilities and increasing statutory obligations, combined with the decline in prices in the international market. A reduction in taxation and fiscal reliefs can help the industry to build up reserves for development. (Paras 4.57-4.58)	Fiscal measures have already been introduced in the Budget of 1970-71. Taxation on Tea Industry cannot be considered in isolation.
64. For the tea estates with exceptionally low profitability who find it difficult to obtain their short term requirements from banks the Committee recommends that the Tea Board may consider guaranteeing the Scheduled Banks such additional advances as may be required for meeting their recurring expenses up to but not exceeding 75% of the value of assets and crop. This limit of 75% should cover all loans of the borrower both short and long-term. The borrower should pay a guarantee commission to the Board and undertake to repay the guaranteed amounts annually. (Para 4.59)	While Government are sympathetically considering schemes to improve profitability of tea estates from time to time, it will not be possible for Tea Board to extend guarantee in regard to short-term requirements for the unprofitable tea estates.
65. The Schemes of financial assistance operated by the Tea Board are preferred by a larger section of the industry as the loans carry a lower rate of interest. The Committee has some recommendations regarding these schemes. (Paras 4.63—4.73)	They need further consideration.
67. The industry should be given a depreciation allowance on its field assets, the tea bushes, on the principles followed in rubber plantations. Taking Rs. 10,925/- the average cost of the planting as the replacement cost per hectare the average economic life of tea as 40 years and an average yield of 1,087 kg. per hectare for India (the average for 1965-67), the depreciation related to output works out to Rs. 25. per 100 kg. of tea produced the depreciation based on this calculation should be allowed as a deduction for Central and agricultural income-tax purposes. This depreciation allowance which should be in addition to the existing development allowance should be funded into a separate account and used for development purposes only. (Paras 4.77—4.81)	The existing arrangements already allow for the cost of replantation to be treated as revenue expenditure. The proposal of allowing depreciation on tea bushes is not acceptable as it would not be practicable to work out a system of depreciation allowance for tea bushes analogous to that prescribed for business assets like plant and machinery.
68. Should the depreciation allowance be acceptable to Government, the replanting subsidy scheme recently announced, need not be continued beyond a period of 10-15 years. (Para 4.82)	Do
69. The concessions allowed under the new Section 35C of the Indian Income Tax Act should be extended to the tea industry. (Paras 4.83—4.85)	The Concession is available to the tea industry if the assessee is a company and it satisfies the conditions prescribed under Section 35C of the Income Tax Act, 1961.

Recommendations	Remarks
79. Government should take an immediate decision regarding internal promotion to gainfully employ the Board's field staff. Alternatively it should take over this staff and relieve the Board of an unnecessary burden. (Paras 5.34—5.36)	The Board has already taken steps to employ the surplus staff
80. The Board's regional office at Cochin and Coonoor may be merged into one and the necessity of having an office at Dharamsala may be reviewed. (Paras 5.38-5.39)	Separate offices at Cochin and Coonoor are necessary and Dharamsala office has been shifted to Palampur.
ANNEXURE-III	
<i>Recommendations of the P. C. Borooah Committee on Tea Industry which have been accepted in principle</i>	
18. The problems of research in tea have grown both in magnitude and complexity but resources for research have not kept pace and are now wholly inadequate. Research organisations should be encouraged and financially supported to intensify their present work. (Para 2.43)	
ANNEXURE-IV	
<i>Recommendations of the P. C. Borooah Committee on Tea Industry which have been noted by Government</i>	
<i>Reference to S. No. in the Summary of Conclusions and Recommendations of the Report of the P. C. Borooah Committee.</i>	
1. The world tea production in 1975 has been tentatively taken to be 1,250 m. kg. (Para 1.1)	
4. The industry is faced with problems in regard to availability of suitable land for extensions. (Para 1.8)	
6. The price of fertilisers fixed by Government from time to time shows an upward trend and would strongly urge that every effort should be made to hold the price line and to ensure that the industry does not have to bear a heavier burden. (Para 1.24)	
17. Both agricultural and industrial research are necessary to bring about improvement in the quality of made tea. (Para 2.6)	
24. Taking advantage of buyer's market in London progressively created by an over-supply, the U.K. buyers, who have the largest single influence on the price level in the international market, have discounted their own rising costs from their bids. This has resulted in the progressive lowering of auction prices. (Para 3.21)	
25. The fall in prices is thus attributed to an easy supply position and over production has balanced consumption at the sacrifice of prices. (Para 3.23)	
35. The emergence of bilateral trading, taken together with the decline in the export/production ratio has inevitably meant that exports to traditional markets have declined. (Para 3.71)	
36. The position in respect of some of our larger markets for tea have been examined. (Paras 3.73—3.91)	
37. It is doubtful if a Government controlled corporation or a consortium of producer will be able to effectively assert itself in the sophisticated markets of the world. Such an organisation, however, if working in co-operation with developing countries may give higher returns and also assist in expanding these markets for tea. (Paras 3.98-3.99)	
39. The total quantity of tea needed for internal consumption by 1970 will be 176 m.kg. which with a production target of 420 m.kg. means that 244 m.kg. will be available for export. (Para 3.101)	
40. The Committee would not recommend a curtailment of internal consumption. The Committee is of the view that a growing internal market is vital for the health of the tea industry in India. (Para 3.101 & 3.106)	
47. The tea trade could do more than they have done in the past for promotion and sale of Indian tea abroad. Government should provide special financial incentives for the export of tea. (Para 3.136)	
48. The Committee welcomes the recent Indo-Ceylon talks and feel that this co-operation will be in the best interests of the tea industry in the two countries. It would be desirable wherever possible to eliminate unnecessary competition in the field of export promotion. (Para 3.137)	
50. The prices at auctions do not bear any relation to the taxes imposed by a producing country as the taxes have to be paid by the producer. Unlike other industries, tea is not able to pass on the burden of taxation to the buyer. Thus the taxes imposed on tea are taxes on production. (Para 4.16)	
51. Although tea is an export-oriented industry, the sales for internal market bear a lesser burden of tax than those for export. (Para 4.16)	
52. The Zonal excise duty paid by the producers at the time tea is cleared from the factory, cannot be passed on to the buyer or consumer and is not refunded on tea exports either. (Para 4.17)	
53. During the last decade, while production has risen by about 19% the revenue from excise duty has increased by 429% (Para 4.19)	
54. Although the basis of the existing zonal classification system (for excise duty) appears to be correct in theory, there are many anomalies. The Committee is of the opinion that a proper study should be undertaken at an early date. (Para 4.20)	
70. The Tea Board is doing very useful work in assisting the industry in various ways. It acts as a useful channel of communication between the industry and the Government. To make it an even more efficient body the Committee has some recommendations to offer. (Paras 5.15—5.17)	
81. The Board should have absolute control over all its staff and activities, particularly in respect of its offices abroad. (Para 5.41)	
ANNEXURE-V	
<i>Recommendations of the Borooah Committee on Tea Industry which have not been accepted by Government</i>	
<i>Reference to S. No. in the Summary of Conclusions and Recommendations of the Report of the P. C. Borooah Committee.</i>	
71. The membership of the Board should be restricted to 30 in number, with persons of high standing in the fields of industry and trade and also public men known to be genuinely interested in the good and well-being of the tea industry. (Para 5.18)	
74. The Board should have a permanent Deputy Chairman and appointment to this post should be left to the Board for recruitment by open selection. (Paras 5.22—5.24)	
75. In the present circumstances, there is no need for the two licensing committees. (Para 5.26)	
78. The Committee considers that the present system of allocating funds to the Board through the consolidated funds is not a satisfactory method. It recommends that the Cess now levied, should continue to be collected by Government, but the proceeds less collection charges should be credited to the Tea Fund account in full to be spent in accordance with the sanctioned budget. This would enable the Board to have a clearer picture of availability of funds to plan ahead for long term projects. (Paras 5.31—5.33)	

**MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND
MINES & METALS**

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 17th August 1970

RESOLUTION

ADVISORY COUNCIL ON NON-FERROUS METALS

No. 13(7)/70-Met.I.—Consequent on the expiry of the term of the First Advisory Council on Non-ferrous Metals, which was constituted *vide* the erstwhile Ministry of Steel Mines & Metals (Deptt. of Mines & Metals) Resolution No. 4(54)Met-67 dated the 30th May, 1968, it has been decided to re-constitute the Advisory Council. The composition of the Council will now be as follows :—

Chairman

1. Minister of Pet. & Chemicals and Mines & Metals.

Members

2. Minister or State in the Min. of PC&M&M (Mines & Metals).
3. Secretary, Deptt. of Mines & Metals.
4. Shri T. N. Lakshminarayanan, Jt. Secy., Deptt. of Mines & Metals.
5. Dr. P. Dayal, Senior Industrial Adviser, Deptt. of M&M.
6. Shri S. S. Kothari, President, Hindustan AI, Corpn. Renukoot, Mirzapur (UP).
7. Shri K. K. Bhasin, General Manager, Aluminium Corpn. of India, Calcutta.
8. Shri P. F. Nugent, General Manager and Director, Indian Copper Corpn., Ghatsila.
9. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Zinc Ltd., Udaipur.
10. Chairman-cum-Managing Director, Bharat Aluminium Co. New Delhi.
11. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Copper Ltd., Khetri.
12. Shri P. M. Menon, Technical Adviser, Bharat Aluminium Co. New Delhi.
13. Shri D. D. Wood, Eyre Smelting Co. Ltd. Calcutta.
14. Shri P. R. Kamani, Managing Director, Kamani Metals & Alloys Ltd., Bombay
15. Shri C. J. Shah, Technical Consultant, Multimetal Ltd., Kota (Rajasthan).
16. Dr. D. P. Antia, Deputy Managing Director, Union Carbide (India) Ltd., Calcutta.
17. Shri F. A. A. Jasdanwalla, Technical Director, Indian Standard Metal Co. Ltd. Bombay-1.
18. Shri S. Vishwanathan, Director (Research) Tata Iron & Steel Co., Jamshedpur.
19. Shri S. K. Chaudhury, Federation of Small Industries of India, New Delhi.
20. Shri B. L. Rajgharia, Chairman, Engineering Export Promotion Council, Calcutta.
21. Shri C. R. Dass, General Manager, Minerals & Metals Trading Corporation, New Delhi.
22. Dr. V. A. Altekar, Director, National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur.
23. Shri B. S. Krishnamachar, Assistant Director-General, Indian Standards Institute, New Delhi.

24. Shri Brahm Prakash, Director, Metallurgical Division, Atomic Energy Department, Bombay.
25. Shri R. K. Sethi, Managing Director, National Industrial Development Corporation, New Delhi.
26. Shri K. L. Nanjappa, Development Commissioner, Small-Scale Industries, New Delhi.
27. Industrial Adviser (Metals) D.G.T.D., New Delhi.
28. Industrial Adviser (Electrical), D.G.T.D., New Delhi.
29. Director, General, Geological Survey of India, Calcutta.
30. Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
31. Dr. L. R. Vaidyanath, Manager, Indian Copper Information Centre, Calcutta.
32. Dr. M. N. Parthasarathy, Indian Lead-Zinc Information Centre, Calcutta.
33. Shri G. D. Binari, President, Indian Non-ferrous Metals Manufacturers Association, Calcutta.
34. A representative of the Federation of India Chambers of Commerce & Industry, New Delhi.
35. A representative of the Planning Commission.
36. A representative of the Ministry of Irrigation and Power.
37. A representative of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.
38. A representative of the Ministry of Communications (P&T Board).
39. A representative of the Ministry of Defence.
40. A representative of the Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.
41. A representative of the Ministry of Finance.

Member Secretary

42. Shri A. Krishnan, Director, Deptt. of Mines & Metals.

2. The term of the above members of the Council will be for a period of two years.

3. The non-official members of the Advisory Council will be entitled to draw T.A. for the journeys to be performed by them by road/rail for attending the meetings of the Council in accordance with the instructions contained in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. F. 6(25)E-IV/59, dated 5-9-1960, as amended from time to time. For the purposes of T.A., D.A., etc. the non-officials will be treated as on par with Government servants of the first grade and they will be paid T.A. in accordance with the revised rates of travelling allowance as laid down in the Ministry of Finance O.M. No. 5(44)E-IV(B)/62, dated 14-8-62, as amended from time to time.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

CORRIGENDUM

No. 3(6)/69-Met.I.—The following corrections may be made in the Government Resolution No. 3(6)/69-Met.I, dated the 12th June 1970 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1 on 12th June 1970 :—

- (1) In line 3 on page 529, the word "paragraph" may be substituted by "paragraphs".
- (2) At the end of line 8 on page 527 oblique (/) may be added after the word "procedure".
- (3) In line . on page 529, the words "make at further" may be substituted by "make a further".
- (4) In line 6 on page 529, the words "metal for very" may be substituted by "metal for every".

M. S. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 21st August 1970

RESOLUTION

No. EL.II.1(8)/69.—The Central Electricity Consultative Council set up by this Ministry's Resolution No. EL.II-1(7)/65, dated 19th January, 1968, read with Resolution of even number dated 12th February, 1968, is hereby reconstituted as under :—

Chairman

1. Union Minister of Irrigation and Power.

Members

2. Union Deputy Minister of Irrigation & Power.

Ministers from States/Union Territories

3. Minister for Irrigation & Power, Orissa.
4. Minister for Public Works Department, Tamil Nadu.
5. Minister for Power Department, Andhra Pradesh.
6. Chief Minister, Himachal Pradesh.
7. Minister for Industries & Power, J. & K.

Members of Parliament

8. Shri Jahan Uddin Ahmed, M.P. (Lok Sabha).
9. Shri B. Narayanan, M.P. (Lok Sabha).
10. Shri Raja Venkatappa Naik, M.P. (Lok Sabha).
11. Shri R. Surrender Reddy, M.P. (Lok Sabha).
12. Shri Dhireswar Kalita, M.P. (Lok Sabha).
13. Shri M. R. Sharma, M.P. (Lok Sabha).
14. Shri Devendra Vijai Singh, M.P. (Lok Sabha).
15. Shri Ram Chandra Ulaka, M.P. (Lok Sabha).
16. Shri P. Venkatasubbaiah, M.P. (Lok Sabha).
17. Shri Brahmananda Panda, M.P. (Rajya Sabha).
18. Shri Prithvi Nath, M.P. (Rajya Sabha).
19. Shri Narayan Prasad Chaudhuri, M.P. (Rajya Sabha).
20. Shri Pandharinath Sitaramji Patil M.P. (Rajya Sabha).
21. Dr. Debiprasad Chattopadhyay, M.P. (Rajya Sabha).
22. To be notified later.

State Electricity Boards

23. Chairman, Assam State Electricity Board.
24. Chairman, Haryana State Electricity Board.
25. Chairman, Madhya Pradesh Electricity Board.
26. Chairman, Mysore State Electricity Board.
27. Chairman, U.P. State Electricity Board.

Representatives of Ministries of Government of India

28. Secretary, Ministry of Irrigation & Power.
29. Vice-Chairman, Central Water & Power Commission.
30. A representative of the Ministry of Railways (Railway Board).
31. A representative of the Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines & Metals (Departt. of Mines & Metals).

32. A representative of the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Deptt. of Iron & Steel).
33. A representative of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Deptt. of Agriculture).
34. A representative of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs (Deptt. of Industrial Development).
35. A representative of the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure).
36. A representative of the Planning Commission.

Representatives of the Undertakings etc.

37. Chairman, Heavy Electricals Ltd., Bhopal.
38. Chairman, Bharat Heavy Electricals Ltd.
39. President, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry or his representative.
40. A representative of the Federation of Electricity Undertakings of India.
41. Chairman, Indian Electrical Manufacturers Association or his representative.
42. The Hon. General Secretary of the Executive Committee of the National Tonnage Club of Farmers.
43. Director (FE&P), Ministry of Irrigation and Power will be the Member-Secretary of the Council.

Chairman may invite any other person to attend the meetings of the Council as he may consider necessary.

2. In order to ensure fairly rapid rotation, the tenure of the Council may be for two years at a time.

3. (a) The Council will consider and make recommendations on the following subjects :

- (i) Matters relating to the generation, supply and distribution of electricity and the services and facilities provided by the electricity undertakings as may be referred to it for consideration, by the Union Minister for Irrigation and Power.
- (ii) Other matters relating to the generation, supply and distribution of electricity and the services and facilities provided by the electricity undertakings which individual Members of the Council may, with the approval of the Chairman, desire to be included in agenda.
- (iii) Any other matter of general public interest or public convenience relating to supply and distribution of power.

- (b) The Council will be purely consultative in character.

- (c) Questions relating to staff, discipline and appointments shall not be brought before the Council.

4. (a) The Council will meet at least once a year.

- (b) The Chairman may constitute committees or sub-committees of the Council to advise the Government on specific problems relating to the services and facilities provided by the electricity undertakings.

- (c) Any member wanting to bring up a subject for discussion should give a clear notice of one month to the Secretary and state briefly the subjects to be discussed. The Secretary will circulate the agenda giving the Members at least 10 days' notice together, as far as possible, with memorandum on each item. Urgent business may, however, be brought forwarded for consideration without notice but with the approval of the Chairman. The Chairman may rule out a subject at his discretion.

- (d) The proceedings of the meetings of the Council will be confidential, but a short summary of the proceedings will be ordinarily prepared and given to the press.

5. The Members of the Council will draw travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Council at the rates fixed by the Government from time to time.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the members concerned, the State Governments, the State

Electricity Boards, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. V. CHARI, Secretary

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND
REHABILITATION**

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st August 1970

No. 31/18/69/LR-II.—In Resolution No. 31/18/69/LR-IV dated 9th December, 1969, *below* Para 2, against S. No. 1 of

Alternate, for Shri T. S. Swaminathan, *substitute* Shri N. M. Vakil.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India Part I—Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administration of Union Territories, Chairman of the Committee on Automation and all others concerned.

P. M. NAYAK, Secretary

